'हूडा' द्वारा 18 लाख रु में निर्मित साइकल ट्रैक लापता

फ़रीदाबाद (म.मो.)। साइकिल चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा के नाम पर करीब दो वर्ष पूर्व 'हूडा' (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने सैक्टर 11 व 12 की विभाजक सड़क पर 1600 मीटर लम्बा व डेढ़ मीटर चौड़ा एक साइकिल ट्रैक बनाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग को बाइपास से जोड़ने वाले इस ट्रैक पर 18 लाख का खर्च दिखाया गया था। मजे की बात यह है कि इस तथाकथित ट्रैक पर कभी किसी ने साइकिल चलते नहीं देखी। यूं भी यह जगह साइकिल चालकों के किसी काम की थी भी नहीं।

विदित है कि शहर की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी साइकिल पर ही निर्भर है। नित्य प्रति अपने काम पर जाने वाले कामकाजी साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। उनका एक बड़ा हिस्सा जान हथेली पर रखकर राजमार्ग, बाईपास तथा अन्य मुख्य सड़कों पर चलने को मजबूर है। उनकी वास्तविक जरूरत के लिए शहर भर में जो साइकिल ट्रैक बनाने चाहिए उसकी बजाये साइकिल ट्रैक का उक्त नमूना पेश करने के नाम पर जनता के 18 लाख रुपये डकार लिये गये। इसकी लागत का हिसाब लगाया जाये तो यह 6 लाख रुपए प्रति किलोमीटर पड़ती है। इस शहर की आवश्यकता के अनुसार हजारों किलोमीटर लम्बे साइकिल ट्रैक की जरूरत है। लुटेरों की सरकार के चोर इंजीनियरों द्वारा बनाये गये उक्त ट्रैक की लागत के हिसाब से यदि सारे ट्रैक बनाये जायें तो यह अरबों रुपए का खेल तो हो ही जायेगा। परन्तु 2-4 साल बाद वे ट्रैक ढूंढ़े से भी नहीं मिलेंगे।

उक्त ट्रैक तो सरकार की कामकाज की एक बानगी मात्र है जिससे पाठक समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा करोड़ों-अरबों के काम करा दिये जाने की घोषणाओं की हकीकत वास्तव में होती क्या है। आये दिन खास कर चुनावी वर्ष में पाठक सरकारी घोषणाओं में सुनते रहते हैं कि इतने सौ करोड़ का यह काम तथा इतने सौ करोड़ का वह काम कर दिया अथवा करने जा रहे हैं, परन्तु वास्तव में वह सब एक हसीन धोखा ही होता है। अभी हाल ही में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने बसंतपुर से महावतपुर की मात्र 23 फीट चौड़ी सड़क का शिलान्यास करते हुए 2 करोड़ लागत की घोषणा की। बीते 3 माह में वे ऐसी सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं कर चुके हैं।

साइकिल ट्रैक की बात तो छोड़िये, पैदल चलने वालों के लिये पूरे शहर में कहीं पटरी तक नहीं है। भले वक्तों में जिस सरकार ने फुटपाथ की व्यवस्था की भी थी उसे मौजूदा राजनेताओं ने बेच खाया। उन सब पर अवैध कब्जे व निर्माण करा दिये। इसकी वजह से लोग मुख्य सड़कों पर चलने को मजबूर होते हैं जिससे राहगीर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं तथा सड़कों पर जाम लगता है।

स्मार्ट सिटी, स्वच्छता अभियान तथा पर्यावरण की दुहाई के नाम पर तरह-तरह के शगूफे छोड़ने के अलावा सरकार ने करना धरना कुछ नहीं।

वोट बैंक के चक्कर में अवैध कब्जे, गांवों में भी

बल्लभगढ़ (म.मो.) सत्ता में बैठे लोग हों या सत्ता में आने को लालायित, जनहित में कोई बेहतर काम करने की अपेक्षा दबंगों को अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण कराने में सहयोग करता अपना वोट बैंक बनाने में अधिक विश्वास करते हैं। अफसरशाह अपनी मलाईदार तैनाती को बचाने व मलाई खाने के लालच में आंखें मूंदे रहते हैं। कई बार शिकायतें मिलने पर भी वे अपनी आंखें बंद रखने का ही उपक्रम करते हैं।

बल्लभगढ़ से सटा गांव सीकरी दिल्ली-मथुरा राजमार्ग पर स्थित होने के चलते यहां की जमीनों की कीमतें काफी ऊंची है। इसलिए यहां पर पंचायती एवं सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे करना काफी लाभदायक रहता है। इस लाभ में से नेताओं व अफसरों को भी अच्छी खासी मलाई खाने को मिल जाती है। गांव के लोग शिकायत कर करके थक जाते हैं परन्तु बीडीपीओ से लेकर डीसी तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यदि इनके कान पर थोड़ी बहुत रेंग भी जाये तो बस दिखावे के तौर पर मामूली कागजी कार्यवाही करके अपनी तैनाती का अहसास भर करा अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

इसी गांव के रणजीत सुपुत्र रोशनलाल ने 2011 में तत्कालीन डीसी प्रवीण कुमार को शिकायत की थी कि कोला नं. 29 के भाग 21 व 22 में ग्राम पंचायत की 16 कनाल यानी 2 एकड़ बेशकीमती जमीन पर सपंच इन्द्रेश पत्नी अनिल कुमार ने अपने दबंग समर्थकों से अवैध कब्जे करवा रखे हैं। इस पर डीसी के आदेश पर एसडीएम वे तहसीलदार ने थ्रोडोलाइट टोटल मशीन द्वारा जमीन की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को तो समझ लिया परन्तु उसके बाद कार्यवाही के नाम पर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया।

ठाकुरों के इस गांव में दो पार्टियां हैं और दोनों के ही मुखिया ठाकुर हैं। एक पार्टी के नेता राजेन्द्र सिंह सुपुत्र गोपीचंद हैं तो दूसरी के मुखिया राम अवतार सुपुत्र एदल सिंह हैं। कभी एक पार्टी का सरपंच बनता है तो कभी दूसरी का। लेकिन दोनों में से किसी भी पार्टी का सरपंच किसी भी अवैध कब्जे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने देता क्योंकि यदि एक कार्यवाही करेगा तो अगली बार दूसरा सरपंच पहले वाले के समर्थकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ही। इसलिये दोनों का सिद्धांत है तू मेरी कमर खुजा मैं तेरी कमर खुजाऊंगा।

इसके चलते गांव के बहुसंख्यक, गरीब, दलित अन्य जातियों के हकूक पर जो कुठाराघात हो रहा है, पंचायत फंड को जिस तरह लूटा जा रहा है उसके प्रति एसडीपीओ से लेकर डीसी तक किसी को भी कोई कानूनी कार्यवाही करने की फुर्सत नहीं है।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा

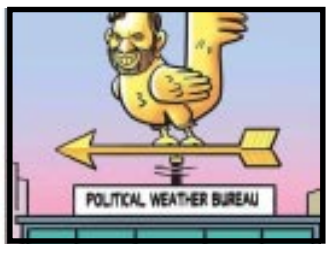

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

23-29 दिसम्बर 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। साम्प्रदायिक एवम् राष्ट्रीय सेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित तथा कुछ स्वार्थी इतिहासकार मध्यकाल और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की घटनाओं व चरित्र को तोड़-मरोड़कर मनगढ़ंत अंदाज में पेश करते रहे हैं और तथ्यों को नजर अदांज करते हुए औरंगजेब को असहिष्णुता व धार्मिक कट्टरता के लिये बदनाम करते रहे हैं, जिससे लोगों के मन में यह धारणा धर कर गई कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, जो मंदिरों को तोड़ता था। 'मुगल बादशाह औरंगजेब का सच सामने लाये भूतपूर्व राज्यपाल में उद्धृत औरंगजेब के फरमानों से औरंगजेब के विरूद्ध झूठे व भ्रामक प्रचार को बेनकाब करते हुए औरंगजेब की तस्वीर का वास्तविक पक्ष सामने लाया गया है।

औरंगजेब ने विभिन्न मंदिरों को फरमान प्रदान किए थे जिनमें उन्हें जागीर और नकद अनुदान दिए गए थे। इनसे स्पष्ट है कि औरंगजेब ने इलाहाबाद के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बनारस के जरामबाड़ी शिव मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के ब्रह्माजी मंदिर, गौहाटी के उमानंद मंदिर, शत्रुन्छाई के जैन मंदिर तथा उत्तर भारत के कई अन्य प्रमुख मंदिरों एवम् गुरुद्वारों को जागीर और नकद अनुदान दिए थे। इसके अतिरिक्त उसने चित्रकूट के मन्दाकिनी तट पर 1683 में 'बालाजी का मंदिर' बनवाया था और उसकी पूजा अर्चना के लिए मंदिर को 330 बीघा बेलगानी कृषि भूमि भी दान की। पहले लोग इसे औरंगजेब का मंदिर के नाम से जानते थे।

साधारणतः कुछ इतिहासकार अहमदाबाद में नगर सेठ द्वारा बनवाए गए चिन्तमणि मंदिर को ध्वस्त करने का तो जिक्र करते हैं परन्तु इस वास्तविकता को छुपा जाते हैं कि औरंगजेब ने उसी सेठ द्वारा बनवाए गए शत्रुन्जया और आबू मंदिरों को काफी बड़ी जागीरें प्रदान की थी। निःसंदेह यह प्रमाणित सत्य है कि औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गोलकुण्डा की जामा मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, परन्तु इसके कारण कुछ और थे जिनको इतिहासकारों ने अक्सर नजर अंदाज कर रखा है।

औरंगजेब के काफिले में से हिन्दू राजाओं की रानियां बनारस में गंगा स्नान करके विश्वनाथजी के मंदिर में दर्शन करके वापिस आई तो उनमें से कच्छ की महारानी गायब थी, जो विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ जी की मूर्ति के ठीक नीचे तहखाने में रोती हुई मिली जिसके साथ व्यभिचार किया गया था और उसके आभूषण भी छीन लिये गए थे। इस पर हिन्दू राजाओं द्वारा नाराजगी और विरोध प्रकट करने तथा उनकी मांग पर औरंगजेब ने विश्वनाथ जी की मूति को कहीं और लेकर जाकर स्थापित करने का आदेश दिया, क्योंकि यह पवित्र स्थत अपवित्र हो चुका है तथा महांत को गिरफ्तार कर लिया गया।

गोलकुण्डा के राजा, जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे जो कुछ ही वर्षो में करोड़ों रुपए में हो गई। तानाशाह ने यह खजाना जमीन में गाड़कर उस पर जामा मस्जिद बनवा दी। पता लगने पर औरंगजेब ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया और गड़ा हुआ खजाना निकालकर उसे जनकल्याण कार्यों में लगाया।

इन फरमानों व घटनाओं से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि औरंगजेब न्याय के मामले में मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं समझता था और कभी यह सहन नहीं करता था कि उसकी प्रजा के अधिकार किसी भी प्रकार से छीने जाएं, चाहे वो हिन्दू हो या मुसलमान। इनसे यह भी पता चलता है कि वह जागीर व नकद अनुदान देने में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करता था।

उपरोक्त फरमानों की मूलप्रति मंदिरों के महंत से लेकर इन तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने फरमानों का ब्योरा एक साथ किसी एक पुस्तक में मिलना कठिन है।

'मुगलों का हिन्दुस्तान' में ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में साबित किया गया है कि राजघरानों (ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, जोधपुर) आदि ने 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के विरूद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की सहायता की थी, उनके बच्चे आज स्वतंत्र भारत में मंत्री, विधायक व सांसद बनते हैं, जबकि टीपू सुल्तान व बाहदुरशाह जफर जैसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई लड़ी उनको केवल मुलसमानों होने के कारण विद्वेष व नफरत की निगाह से देखा जाता है। मोदी सरकार के शासनकाल में तो मुगलों से संबंधित स्थानों व सड़कों का नाम बदला जा रहा है, जबकि मुगलकाल में ''रामपुर'', ''सीतापुर'' व ''अयोध्या'' आदि नाम बदस्तूर जारी रहे। स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान जिन लोगों व संस्थाओं 'जैसे संघ परिवार ने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध किसी संघर्ष में भाग नहीं लिया वे आज ''भारत माता की जय'' और वंदेमातरम'' कहकर देशभक्त बन जाते हैं।

आईपीएस रजनीश रॉय, द्वारा सोहराबुद्दीन का फर्जी एनकाउंटर बोस की जांच करने के बाद इसमें लिप्त गुजरात के आईपीएस तत्कालीन डीआई डीजी बंजारा, एसपी राजकुमार वांडियन और राजस्थान के आईपीएस दिनेश एमएन, डीआईजी अभय चासुमा तथा तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने, असम में चिरांग जिले के सिमालगुड़ी इलाके में फर्जी मुठभेड़ में दो व्यक्तियों की हत्या की जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, असम सरकार व सीआरपीएफ से जवाब तलब करने तथा झारखंड में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट देने से मोदी सरकार नाराज हो गई और परेशानियों से मजबूर होकर रॉय ने इस्तीफा दे दिया, जिसका 'सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का खुलासा करने वाले आईपीएफ अधिकारी रजनीश राय ने इस्तीफा दिया' में खुलासा किया गया है। मोदी सरकार व अमित शाह की अपने अनुकूल निर्णय करवाने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी तरीके अपनाये जाएं जैसे धमकाना, प्रलोभन देना आदि। इसके ज्वंलत उदाहरण है सुप्रीम कोट के चीफजस्टिस सदाशिवम ने सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह के खिलाफ एफ आईआर को रद्द कर दिया और उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया, सीबीआई अदालत द्वारा सोराहबुद्दीन कांड के कातिलों को बरी करना, सीबीआई को विशेष जज जेटी उत्पट द्वारा अमित शाह को समन करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरूद्ध उत्पट का तबादला करना, गुजरात के एसपी राकेश अस्थाना द्वारा गोधरा कांड की जांच रिपोर्ट सत्ता के अनुकूल देने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसे सीबीआई में लाना आदि।

'मझोले और छोटे उद्योगों में 35 लाख नौकरियां गई तो मोदी शाह किन 7 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे - मोदी सरकार नौकरियों का विज्ञापन निकाल रही हैं, नौकरियां दी नहीं जा रहीं, उन्हें भटकाया जा रहा है' में मोदी शाह द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के झूठे दावों और नोटबंदी व जीसएटी के कारण आर्थिक रफतार धीमी हुई है जिसका बुरा प्रभाव नौकरियों पर पड़ा हैं बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद अमित शाह द्वारा झूठा दावा किया जा रहा है कि मुद्रा लोन के कारण करोड़ों लोगों को स्व-रोजगार मिला हैं जबकि मीडिया मोदी-शाह-अरूण जेटली के झूठे दावों व आंकड़ों को पेश कर जनता को भ्रमित कर रहा है।

समाज में साम्प्रदायिकता भडकाने वाले योगी आदित्यनाथ के विवादित भाषण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात और परवेज परवाज लम्बे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब मोदी शाह की तरह योगी व उनका कुनबा खुद को बचाने के लिए परवेज के खिलाफमुकदमें पर मुकदमा दर्ज करके राजनीतिक षडयंत्र के तहत कार्यवाही कर रहे हैं, जिसकी 'योगी को कटघरे में खड़ा करने वाले पर मुकदमें पर मुकदमा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन लेकिन...' में विवेचना की गई है। यह मोदी-शाह-योगी की कार्यशैली है कि यदि कोई उनकी नीतियों का विरोध करे और पीछे नहीं हटे तो उसके विरूद्ध राजनीतिक षडयंत्र रचकर उसे परेशान किया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाये।

बुलन्दशहर में हिंसा के दौरान पुलिस इन्सपैक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने पर योगी आदित्यनाथ द्वारा इन्सपैक्टर की हत्या की बजाए गाय को ज्यादा महत्व देने पर कई पूर्व नौकरशाहों ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग की। नसीरूद्दीन शाह ने इस घटना पर कहा कि देश में गाय की जान की कीमत एक पुलिसवाले से ज्यादा हो गई है तथा लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उन्हें खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक जहर फैलाया जा रहा है जिसे रोकना मुश्किल है। संघ परिवार से संबंधित लोगों ने नौकरशाहों के व्यक्तव्य को तो नजरअंदाज कर दिया, परन्तु नसीरूद्दीन के विरूद्ध आग-बबूला हो गए और उनको भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कहा तथा हिन्दूवादी संगठनों ने तो अजमेर में उनका कार्यक्रम ही नहीं होने दिया, जिसका 'नसीरूद्दीन शाह की बातों का जवाब नहीं है, हनुमान की जाति जरूर जानते हैं' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। नसीरूद्दीन के बयान का ठोस जवाब न दे पाने पर संघ परिवार ने जनता को भ्रमित करने और मीडिया में चर्चा को भटकाने के लिए हनुमान की जाति का मुद्दा उछाल दिया।

पहली बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कोई नया राज्य जीतने की बजाए तीन राज्य गंवाने के कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस हद तक दबाव में आ गई है कि वह अपने सहयोगी दलों से लोकसभा चुनावों के लिए ले-देकर सीटों का तालमेल करें। पुराने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएसएसपी) का एनडीए से अलग होने पर रामविलास पासवान व चिराग पासवान ने बिहार में सीटों के बंटवारे के लिए भाजपा व अमित शाह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 'बहुत पलटी मार रह इस बार यह राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक पिता पुत्र की जोड़ी फिर से एनडीए में रूकने को तैयार' में पासवान को लोकसभा चुनाव से पूर्व राज्यसभा में भेजा जायेगा। परिणामस्वरूप पासवान एनडीए में बने रहेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति को टरकाए जा रही है, उसी तर्ज पर हरियाण में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति होने के बावजूद खट्टर सरकार डीजीपी बलजीत सिंह सिंधू के रिटायर होने के तीन माह बाद भी नया डीजीपी लगाने में लापरवाही कर रही है, जिसकी खट्टर के डीजीपी दिहाड़ी पर' में समीक्षा की गई है।